आईआईजीसी २०१७ मे डीआरसी प्रतिनिधियों तथा भारतीय बुलियन हितधारकों की विशेष बैठक

भारतीय गोल्ड उद्योग काफी तेजी से बदल रहा है। उद्योग मे रहें सुधारों के चलते जहां यह बेहतर अनुपालन मे शामिल हो रहा है तथा उससे नये अवसर भी पैदा हो रहें है वहीं अनेक व्यवसायिक चुनौतियां भी देखने को मिल रही है।

गोल्ड रिफायनिंग क्षेत्र भारतीय गोल्ड उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र बिंदु है। यहां पर लगभग ३० रिफायनरियां है जिसमे से एक एलबीएमए द्वारा मान्यताप्राप्त है। एलबीएमए मान्यताप्राप्त रिफायनरियों के लिये डोरे की सोर्सिंग कोई मुश्किल कार्य नही है लेकिन अन्य के लिये बड़ी कठिनाई का कार्य है। इसके पीछे अनेक कारण है लेकिन उनमे सबसे प्रमुख यह है कि उद्योग को स्थायी रहने की दिशा मे बढ़ना होगा। डोरे की सोर्सिंग मे आने वाली कठिनाईयां अनेक की संख्या मे है जिसे दूर करने के लिए भारतीय हितधारकों तथा गोल्ड माइनिंग कंपनियों के बीच प्रभावी बातचीत की आवश्यकता है।

आईआईजीसी इस तरह के बातचीत के लिये एक आदर्श मंच है। एक सामान्य औद्योगिक मंच के रुप मे आईआईजीसी हमेशा से ही व्यवसाय के लिये बेहतर संभावनायें प्रदान करता आ रहा है और इसी कारण से इस सम्मेलन का आयोजन एक दशक से सफलतापूर्वक हो रहा है। आईआईजीसी ने यह महसूस किया कि भारतीय रिफायनरों को कच्चे माल के लिये एक विश्वसनीय स्त्रोत की आवश्यकता है और इसी को ध्यान मे रखकर डीआरसी तथा घाना के सरकारी अधिकारियों और भारतीय उद्योग प्रतिनिधियों के बीच बेहतर आपसी समझ के लिये एक विशेष बंद–दरवाजा बैठक का आयोजन किया गया था।

डीआरसी के साथ बैठक

प्रतिनिधि मंडल

माननीय श्री बुलिन्डि अपोलिनेअर, खनन मंत्री, सुड किवु, डीआरसी

श्री याम्बा लफ्फा लमबेन्ग, सीईईसी

श्री मौरिक मियेमा मियेमा, सीईईसी

श्री फ्रेडि मुआम्बा कनयिम्कु, सीईईसी

श्री अलेक्स माइकेन्ड्रिज पेन्गे, सीईईसी

मुख्य चर्चा बिंदु

डीआरसी मे लगभग २ टन गोल्ड का हर माह उत्पाद छोटे तथा कारीगरी माइनों के द्वारा किया जाता है, इसके अलावा संगतःइत क्षेत्र मे किबाली व अन्य माइनें भी गोल्ड का उत्पादन करती है।

कान्गो की सरकार के द्वारा पड़ोसी देशों को गोल्ड की तस्करी रोकने के लिये पहले ही उपाय किये जा चुके है। सरकार को यह विश्वास है कि गोल्ड की तस्करी पर नियंत्रण हो चुका है तथा स्थानीय हितधारकों को भी सावधान किया गया है कि वे देश के सीमावर्ती क्षेत्रों से गोल्ड की खरीदी पर नजर रखें।

कान्गो की सरकार गोल्ड माइन के क्षेत्र मे निवेश का स्वागता करता है। कंपनियों के द्वारा उनके निवेशित पूंजी की वापसी होने तक सरकार के द्वारा कोई टैक्स नही लगाया जायेगा।

सुड किवु सरकार, जो कि देश के पूर्वी भाग का राज्य है, ने "गोल्ड कलेक्शन पॉइन्ट" की स्थापना की है जहां कारीगरी माइनर अपना गोल्ड जमाकर मूल्य प्राप्त कर सकते है। इस गोल्ड को बाद मे अधिकारिक स्त्रोतों के द्वारा निर्यात किया जायेगा जिससे गोल्ड रिस्पान्सिबल सोर्सिंग दिशानिर्देश का अनुपालन हो सकेगा। वैश्विक संस्थाओं के द्वारा कान्गो को खनिजों की खरीदी के लिये "विवादित क्षेत्र" की श्रेणी मे रखा गया है, उम्मीद है कि सरकार के इस कदम से छवि सुधारने मे मदद मिलेगी।

कान्गो मे अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा स्थापित है तथा ब्रिन्क्स प्रिशियस मेटल्स के परिवहन के लिये प्रमुख सेवा प्रदाताओं मे से एक है। अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के लिये बैंकिंग व्यवस्था पर्याप्त है।

यदि आप किसी प्रतिनिधि सदस्यों के साथ संपर्क करना चाहते है तो कृपया हमे debajit@bullionbulletin.in पर ईमेल करें।